मुद्रीकरण एवं नवीकरण

मुद्रीकरण एवं नवीकरण की उक्ति हमारे मानवीय प्रधानमंत्री ने उद्घोषित किया है। इसे अभी भी केंद्र सरकार "वेद मंत्र" की तरह इस्तेमाल कर रही है। इसके तहत इनकी धारणा है कि लोक सम्पत्ति की बिक्री कर उससे प्राप्त धन का उपयोग देश के नवनिर्माण में लगाया जायेगा। यह ठीक उसी प्रकार की बात हुई कि घर में रखी हुई कि सम्पत्ति (चांदी–सोना) को बेचकर घर की दीवारों को सजाया जाये। प्रधानमंत्री को डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एवं लोक संपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आयोजित बेबिनार में उक्त उक्ति को उद्घोषित किया है। यह विभाग नीति आयोग द्वारा किये गये निर्णयों के अनुकुल राष्ट्रीय लोक संपदा को निजी हाथों को बेचने एवं सौंपने की कार्यवाहक ईकाई है। यह अभी सरकार की प्राथमिकता बन गई है।

प्रधानमंत्री ने पूर्व में अपने विदेशी दौरों के वक्त यह अन्य देशों की सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। आज पुनःजब वे विनिवेश के पक्ष में तर्क देते हुए कहा कि इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार का काम व्यापार में बने रहना नहीं है। उन्होंने बताया कि सभी सौ की संख्या में सामरिक एवं गैर सामरिक सभी कंपनियों की बिक्री की जायेगी।

घर की संपदा को बेचकर इसे आमदनी बनाने की अर्थनीति को कोई भी भारतीय मंजूरी नहीं दे सकता। यह राष्ट्र के लिए एक खतरनाक सोच हो सकती है। यह हमारी आत्मनिर्भरता एवं स्वदेशी की भावना के प्रतिकूल है। यह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय धन्ना सेठों के हित में होगी।

इसके दूरसंचार, सैन्य सुरक्षा आदि क्षेत्र की संपदा को बेचना तथा वित्तीय संस्थानों का नीजिकरण करने की बातें जनमानस में चिंता एवं आक्रोश को बढ़ा रही है। इन हालातों के विरूद्ध श्रमिक समुदाय लगातार संर्धष कर रही है। अभी 15 मार्च 2021 से वित्तीय संस्थानों के अधिकारी एवं कर्मचारी चार दिनों की पूर्णतः हड़ताल किये हैं और लगातार संघर्ष जारी है। परंतु सरकार किसानों सहित समस्त जन आंदोलनों को सोची–समझी रणनीति के तहत नजरअंदाज करते जा रही है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ग्राह्य नहीं प्रतीत होता है। रक्षा बैंच के कर्मचारी, बैंक कर्मी, बीमा कर्मी सभी संघर्षरत है। सरकार मौन होकर अपना लक्ष्य को पूरा करने में कटिबद्ध है।

किसान आंदोलनरत हैं। इन्हें राष्ट्र का अन्नदाता कहा जाता है परंतु ये गत चार माह से सड़कों पर हैं और सरकार इसे नजरअंदाज कर रही है। सरकार पूर्ण रूप से पांच राज्यों के चुनाव को अपने दल के लिए जीत लेने के लिए कवायद कर रही है। लोकतंत्र में किसी दल के विजय पराजय से हमारा सरोकार नहीं है। परंतु राष्ट्र के ज्वलंत सवालों पर आखिर जनता की निगाह किस पर उठेगी यह की यह समझने की जरूरत है।

यह घोर आश्चर्य की बात है कि भारतीय जीवन बीमा निगम जो केंद्र सरकार का एक उपक्रम है, को भी सरकार निजीकरण के रास्ते पर ले जाना चाहती है। यह निगम बीमा क्षेत्र में सत्तर प्रतिशत बाजार पर कब्जा रखती है। पिछले 22 सालों से निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों को इस क्षेत्र में प्रवेश दिये जाने के बावजूद जीवन बीमा निगम सर्वोपरि संस्थान है तथा इसकी कुल पूंजी देश के सबसे बड़े धन्नासेठ श्री मुकेश अंबानी की पूंजी से तीन गुना है। यह संस्थान विपदाओं में या राष्ट्रीय विकास कार्यों में सरकार को भारी आर्थिक योगदान देती है। सरकार की हठधर्मिता समझ से परे है कि सोने का अंडा देने वाले लोक उपक्रमों, वित्तीय संस्थानों आदि को समाप्त कर निगमित घरानों का एकाधिकार जमाने की व्यवस्था किसके हित के लिए कर रही है।

इस मुद्रीकरण एवं निजीकरण की होड़ की ओर ध्यान देने से ऐसा लगता है कि सरकार अपने अर्थव्यवस्था को संभालने में हुई विफलता को व्यवस्थित करने के लिए सभी लोक उपक्रमों, वित्तीय लोक उपक्रमों को निगमित

घरानों के हाथ सौंप देना चाहती है। आम जनता एवं साध ाारण श्रमिक समुदाय अर्थशास्त्र के ज्ञाता नहीं हैं परंतु वे अपने अनुभव के आधार पर यह समझते हैं कि राष्ट्रीय संपदा को बेचकर इसे समाप्त कर देश का नव–निर्माण नहीं किया जा सकता और इसी कारण श्रमिक एवं किसान लगातार संघर्षरत हैं। देश की आजादी के बाद श्रमिकों ने इन उक्त संस्थानों के मार्फत न केवल अपनी आजीविका पाई है बल्कि राष्ट्र निर्माण का कार्य भी किया है। आज का भारत और आज की खुशहाली इन्हीं की प्रतिबिम्ब है। स्थिति बहुत नाजुक और भयावह होती जा रही है जो श्रमिकों को प्रभावित कर रही है और यह आम जनता को भी अपने आगोश में लेती जा रही है।

दूरसंचार क्षेत्र का एकमात्र विभाग दूरसंचार विभाग को सन् 2000 में निगम में परिवर्तित किया गया। उस समय यह कहा गया कि निगम बनाने से राष्ट्रीय दूरसंचार नीतियों का त्वरित प्रतिपादन हो सकता है। इस निगम ने सरकार के अपेक्षा के अनुकूल कार्य भी किये। परंतु अभी जो हालात बन चुके हैं उससे सरकार की छिपी नीतियों का खुलासा हो रहा है। अब यह स्पष्ट हो रहा है कि दूरसंचार विभाग का निगमीकरण निजी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। पहले दूरसंचार क्षेत्र में बहुत ही हल्की विनिवेश की व्यवस्था की गई जो निरंतर बढ़ते हुए आज शत–प्रतिशत कर दी गई है।

भारत सरकार का इकलौते दूरसंचार उपक्रम की हालात आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है।

बीएसएनएल भारत की जनता का विश्वास है और इसे कनेक्टिंग इंडिया के नाम से जानते हैं। कंपनी की निरंतर हालात के खिलाफ जब इसके कर्मचारियों ने लगातार संघर्ष किया और जनमानस में जब यह सवाल कौंधने लगा तो सरकार ने 23 अक्तूबर 2019 को भारत के मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से इस कंपनी के लिए एक विशेष उन्नयन पैकेज की घोषणा की। उस घोषणा के प्रमुख बिंदुओं में कर्मचारियों को वी.आर.एस. के तहत पचास प्रतिशत को बाहर कर देने के बाद बचे हुए कर्मचारियों को वेतन का भुगतान भी समय से नहीं किया जा रहा है। गैर कानूनी ढंग से कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते का भुगतान रोक दिया गया है।

उस उन्नयन पैकेज का द्वितीय बिंदु है बी.एस.एन. एल के लिए 4–जी स्पेक्ट्रम का आवंटन जो आज तक कंपनी को उपलब्ध नहीं है। आज इस कंपनी के उपभोक्ता पलायन कर रहे हैं तथा बेसिक सेवाएं बाधित हो रही है। कर्मचारियों की घोर कमी को आउटसोर्सिंग के द्वारा पूरा करने की योजना जमीन पर बेमानी हो रही है। उपभोक्ता परेशान हैं। सरजमीन के हालात विपरीत हैं परंतु मुख्यालय को भारी भरकम रिपोर्ट भेजें जा रहे हैं। समाचार आते रहते हैं कि बी.एस.एन.एल. को सुदृढ़ किया जा रहा है। जनता के आंखों में धूल झोंकी जा रही है।

कुल परिस्थितियां यह बताती हैं कि सरकार लोक उपक्रम बी.एस.एन.एल. के लिए नहीं अपितु निजी कंपनियों का हित कर रही है। किसानों के लिए तीन कृषि कानून और श्रमिकों के लिए सभी श्रम कानूनों को हटाकर चार कोड लाकर सरकार ने किसानों एवं श्रमिकों के सामने अंधकार की स्थिति पैदा कर दी है।

हम श्रमिक संगठन के लोगों के सामने बाध्यता है कि हम इस स्थिति पर गंभीरता से विचार करें। अपनी पूर्ण एकता कायम करना समय की पुकार है। हमने बी.एस.एन. एल. बचाओ देश बचाओ के नाम पर अनेकों संघर्ष किये हैं। अब समय की पुकार है कि हम समस्त राष्ट्रीय श्रमिक समुदाय के गोलक्की में शामिल होकर उनके साथ संयुक्त संघर्ष का सूत्रपात करें। अब लोक उपक्रम बचाओ, देश बचाओ के नारे के साथ हमें अग्रसर होना होगा।

एन.एफ.टी.ई अपने विरासत के अनुकुल इसमें अग्रण ाी भूमिका.अदा करने कों तत्पर हैं पुर्ण एकता बनाने एवं संर्धष कि अगली कतार में रहकर हम श्रमिकों के हित एवं लोकउपक्रमों कि रक्षा के लिए कटिबद्व है।